महत्वपूर्ण एवं खास

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 29 जुलाई को

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती गोमती साय की अध्यक्षता में 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे से कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आहूत की गई है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

विकास सहायक के 2 संविदा पद के लिए 11 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों में से विकास सहायक के 2 पद संविदा भर्ती के लिए 11 अगस्त 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक नियत तिथि को शाम 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिले के वेबसाईट में अवलोकन कर सकते है।

पहुंच विहीन छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने शिक्षक करें कार्य-सीईओ सुचौधरी

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
जिला पंचायत सीईओ सुऋचा प्रकाश चौधरी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई में रूकावट न आये इसके लिए सभी को सामुहिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों को शासकीय दिशा-निर्देशों के बीच कैसे पढ़ाई से जोड़े रख सकते है इसके लिए नवाचार लाते हुये शिक्षण कार्य जारी रखें। सीईओ सुचौधरी ने बैठक में जिले में पहुंच विहीन छात्रों को पढ़ई तुंहर दुआर योजना से जोडने् के लिये विस्तार से चर्चा की। जिन बच्चों तक यह योजना नहीं पहुंच पा रही है उन तक वैकल्पिक रूप से पढ़ई तुंहर पारा मोटर सायकल व माइक के द्वारा पढ़ाई करवाने के निर्देश दिये। साथ ही अधिकारियों से ऐसे छात्र जिनके पास स्मार्ट फोन है, जिनके पास कीपेड फोन है तथा जिनके पास किसी भी तरीके का फोन नहीं है इसकी अलग-अलग संख्यात्मक जानकारी तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने सभी शिक्षकों को शत-प्रतिशत स्मार्ट फोन का उपयोग करने के निर्देश दिये। ऑनलाईन क्लास जनरेट करने में आ रही समस्या को देखते हुये यूट्यूब में ट्यूटोरियल वीडियो पोस्ट कर उसे अधिक से अधिक शेयर करने के लिए भी कहा। सीईओ सुचौधरी ने अधिकारियों से कहा कि पढ़ई तुंहर दुआर को शुरू हुए लगभग साढ़े तीन-चार माह हो चुके है अत- इस अवधि की पूरे जिले में प्रगति की समीक्षा की जाए तथा एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आगे की पढ़ाई जारी रखे। उन्होंने शास.कन्या उच्च.माध्य.विद्यालय (पुत्रीशाला) तथा शास.नटवर हायर सेकेण्डरी उच्च.माध्यमिक विद्यालय द्वारा अपेक्षित संख्या में ऑनलाईन क्लासेस नहीं लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अनुपस्थित पाये गये प्राचार्यो व संकुल स्त्रोत समन्वयकों व अन्य को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। इस बैठक में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक रमेश देवांगन, सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल, सहायक संचालक सुतरसिला एक्का, भूपेन्द्र पटेल, भुनेश्वर पटेल, शैलेन्द्र कर्ण के साथ जिले के हाई तथा हायर सेकेण्डरी व अन्य स्कूलों के प्राचार्य, बीईओ, बीआरसी व संकुल स्त्रोत समन्वयक भी जुड़े।

जिला मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियो की अनुपस्थिति में संयोजन अधिकारी की नियुक्ति

कोरबा (आरएनएस)। प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश या अन्य कारणों से जिले से बाहर रहने पर संयोजन अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। संजय अग्रवाल अपर कलेक्टर के संयोजन अधिकारी मती प्रियंका महोबिया अपर कलेक्टर होंगे। मती प्रियंका महोबिया के संयोजन अधिकारी संजय अग्रवाल होंगे। इसी प्रकार कुंदन कुमार सीईओ जिला पंचायत के लिंक अधिकारी संजय अग्रवाल, एस. जयवर्धन आयुक्त नगर निगम कोरबा के संजय अग्रवाल, मती कमलेश नंदिनी साहू संयुक्त कलेक्टर के लिंक अधिकारी अजय उरांव डिप्टी कलेक्टर कोरबा होंगे।

राजस्व अधिकारी बिना किसी दबाव के नियमों के अनुरूप सेवा भाव से कार्य करे

ग्रामीणों का मिसल की नकल अब तहसील कार्यालयों से प्राप्त होगी-कलेक्टर भीम सिंह

कलेक्टर ने की सभी एसडीएम और तहसीलदार के कार्यों और और लंबित प्रकरणों की समीक्षा

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना की समीक्षा करते हुये जिले के सभी एसडीएम और सभी तहसीलदार को कहा कि जिले में 95 प्रतिशत किसानों का पंजीयन हो गया है शेष 5 प्रतिशत किसानों का पंजीयन करें और जिले के शत-प्रतिशत पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिलावे। कलेक्टर सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी, पटवारी तथा कृषि विभाग के आरईओ एक साथ मिलकर इस कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें।

साथ ही जिन किसानों को इस योजना से अपात्र पाया गया है जैसे शासकीय नौकरी, 10 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन अथवा आयकर दाता, मृतक भू-स्वामी के वारिसों का नाम दर्ज नहीं होने या अन्य कारणों सहित पूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया जाये।

उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों के लिये यह जानकारी संख्यात्मक हो सकती है परंतु एक ग्रामीण किसान को 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अत- इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करें और जिन किसानों का पंजीयन आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा नाम के अक्षरों में अंतर (स्पेलिंग मिस्टेक)के कारण त्रुटिपूर्ण हो उसे भी शीघ्र दूर किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया किसानों को प्रलोभित कर उन्हें अनुचित लाभ दिलाने के लिए गलत ढंग से किसानों का पंजीयन करने वाले व्यक्तियों और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर)के संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करावे।

कलेक्टर भीम सिंह ने सामुदायिक वनभूमि अधिकार पट्टा तथा व्यक्तिगत वनभूमि अधिकार पट्टा के प्रस्तावों की प्रगति के बारे में राजस्व अनुविभाग के अनुसार समीक्षा करते हुये कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप सामुदायिक वन अधिकार पट्टा शीघ्र प्रदान किया जाना है अत- इसके प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करवाकर एक सप्ताह में कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर सिंह ने राजस्व अधिकारियों को नजूल जमीन पर रहने वाले व्यक्तियों के पट्टे का नवीनीकरण कर और फ्री होल्ड किये जाने और आवासीय पट्टे पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार नवीनीकरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने नजूल भूमि पर अवैध रूप से कब्जाधारियों का वास्तविक सर्वेक्षण कर नियमानुसार राशि जमा करने के नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये। राज्य शासन द्वारा अवैध कब्जाधारी व्यक्तियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिये अच्छा अवसर प्रदान किया गया है।

वन अधिकार पट्टे ने खोला बिरहोर केंदाराम के लिए तरक्की का रास्ता

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान कर शासकीय योजनाओं से जोड़ते हुये उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लम्बे समय से वन्य क्षेत्रों में निवासरत लोगों को उनकी पैतृक भूमि व निवास के वन अधिकार को शासकीय दस्तावेज में दर्ज करने से लोगों के जीवन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति में शुमार बिरहोर जनजाति के केंदाराम बिरहोर जो कि रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम खलबोरा में रहते है। केंदाराम मूलत- इसी विकासखण्ड के ओंगना ग्राम के निवासी थे जो सन् 1980-81 में खलबोरा आकर बस गए। शुरूआत में जीविकोपार्जन के लिये वन्य संसाधनों पर ही निर्भर रहे। धीरे-धीरे उन्होंने वन क्षेत्र के बीच जमीन साफ कर खेती प्रारंभ की और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज उगाना शुरू किया और सन् 1984 से नियमित रूप से कृषि कार्य कर रहे है। किन्तु जमीन कहीं दर्ज नहीं होने की वजह से शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था और वह मौसम आधारित एक फसलीय खेती ही कर पा रहे थे जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी

तथा उन्हें खाद व बीज भी खुले बाजार से लेना पड़ रहा था।

शासन की योजना से उन्हें 1.580 हेक्टेयर काबिज भूमि में कृषि कार्य हेतु वन अधिकार पत्र मिला। जिसने उनकी उन्नति के मार्ग खोल दिये। वन अधिकार पत्र मिलने के पश्चात शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण आय संवर्धन से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। सिंचाई हेतु कुआं, बोरवेल (सोलर पम्प)डबरी निर्माण कार्य हुआ। उच्च गुणवत्ता के बीज एवं खाद भी शासन द्वारा दिया जाने लगा। मनरेगा के तहत भूमि का समतलीकरण किया गया। जिससे वह खरीफ व रबी दोनों फसल लेने लगे। केंदाराम खरीफ में धान की फसल उगाते है तथा रबी में मक्का व आलू की उपज ले रहे है। उन्होंने इस खरीफ वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 80 हजार रुपये का धान बेचा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर राशि की प्रथम किश्त भी उन्हें मिल चुकी है। आलू व मक्का से 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी भी उन्हे पृथक से होती है। इस राशि से अपनी आजीविका स्त्रोत को बढ़ाते हुये 20×20 डबरी में मछली पालन भी शुरू किया है व साथ ही बकरी पालन का कार्य भी प्रारंभ किया है। शासन की इस योजना ने केंदाराम को आर्थिक रूप से पहले से काफी सशक्त बनाया है।

केंदाराम कहते है कि पिछले 40 वर्षो से खेती कर रहे जमीन का मालिकाना हक मिल जाने से बड़ा सुकून है। इससे वह अपनी उपज आसानी से बेच सकते है। जमीन से बेदखल किये जाने का भय भी मन से समाप्त हो गया है। बिरहोर जनजाति मूलत- वनांचलों में रहकर अपनी जीवन निर्वाह के लिए जानी जाती है। किन्तु वन अधिकार पत्र ने उन्हें खेती-किसानी से जोड़ते हुये समाज की मुख्य धारा में शामिल कर दिया है। अपने पोतो को छात्रावास में रखकर अच्छी तालिम भी दिलवा रहा हूं। इससे वे आगे चलकर कुछ अच्छा कर सके। जीवन में इस बदलाव के लिये शासन का हमेशा आभारी रहूंगा।

संसदीय सचिव ने किया सोशल मीडिया सेंटर का शुभारंभ

महासमुंद (आरएनएस)। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस भवन के पास सोशल मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान युवा नेता आवेज खान के नेतृत्व में युवाओं ने कांग्रेस प्रवेश किया। सभी युवाओं का संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया।बुधवार को कांग्रेस भवन के पास युवा नेता आवेज खान द्वारा सोशल मीडिया सेंटर का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित था। मुख्य अतिथि संसदीय सचिव श्री चंद्राकर थे। अतिथि के रूप में विजय साव, बादल मक्कड़, राजू कृष्णानी, हरबंश मक्कड़, अशरफ धनवानी, अब्दुल जावेद जाफरी, रईस अख्तर, अनूज सोनी, आबिद खान बावनकेरा, वकार अली मौजूद थे। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने सोशल मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। बाद इसके आवेज खान के प्रयास व पहल पर गोकूल, थानसिंह, ईश्वर, ताराचंद, भकलू, अजय, अशोक, नंदू, बिहारी, नीलकमल, कमल, गुमान, रोशन, नरेश, शिवम, अरविंद, गणेश आदि ने कांग्रेस प्रवेश किया।

आबकारी विभाग की टीम ने पडिग़ांव के गौतम साहू के घर से 14 लीटर महुआ शराब किया जप्त

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
कलेक्टर भीम सिंह ने आबकारी विभाग को जिले में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं तस्करी पर कड़ाई से रोकथाम लगाने के लिए निर्देशित किया था। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को तमनार क्षेत्र में शराब बनाकर बेचने की सूचना मिली जिस पर सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती मंजूरी कसेर के दिशा-निर्देश पर आबकारी उप निरीक्षक आशीष उप्पल ने तमनार ब्लाक के पडिग़ांव में गौतम साहू के घर की तलाशी लेने पर एक कमरे से 14 प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में एक-एक लीटर महुआ शराब कुल 14 लीटर बरामद हुई। गौतम साहू को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जिला न्यायालय रायगढ़ में पेश कर जेल दाखिल किया गया। आबकारी वृत्त-घरघोड़ा में माह जुलाई 2020 में अब तक 6 प्रकरण तथा आबकारी वृत्त रायगढ़ शहर में 7 प्रकरण दर्ज किये जा चुके है। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक रघुनाथ पैकरा, पित्रूस मिंज, हेम प्रकाश डनसेना, कहरू राम भगत, प्रभुवन बघेल और वाहन चालक संतोष उपस्थित थे।

हथियार से ज्यादा कारगर कैमरे ,तीसरी आँख की पहरेदारी जरुरी

सुरक्षा के पैमाने तय करने मे सीसीटीवी की अनदेखी पड़ रही भारी

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
कहने को तो शहर प्रशासनिक और पुलिस के रिकार्ड मे संवेदनशील जिलों की श्रेणी मे शामिल है किंतु यह संवेदनशीलता व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र मे कहीं कहीं ही नजर आती है। खासकर शहर समेत जिले भर मे दिनदहाड़े घटने वाली आपराधिक वारदातों के रोकथाम और नियंत्रण की दिशा मे कई जरुरी संसाधनों की कमी आज भी बनी हुई है,जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन के तमाम दावे भी लोगों मे सुरक्षा का एहसास पुख्ता नहीं कर पा रहे। दरअसल विकास की ओर अग्रसर रायगढ़ जिले मे बढती आबादी के फलस्वरूप आपराधिक गतिविधियों मे वृद्धि पर कारगर नियंत्रण के लिए नगर को तीसरी आँख की निगरानी मे रखना आवश्यक हो गया है।लेकिन शासन - प्रशासन इस दिशा मे आज तक गंभीर नहीं हुआ है। यही वजह

है कि जिला मुख्यालय समेत जिले भर के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी नहीं होने से लोगों मे खौफ और पुलिस की परेशानी दोनो बढ रही हैं।

गौरतलब है कि जिले मे बढ़ती वारदातों को लेकर आम लोगों ने अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देना शुरु कर दिया है।घरों से लेकर आफिस व संस्थाओं मेअब सीसीटीवी कैमरे की मांग बढ़ गई है।स्थानीय कारोबारियों की मानें तो हर रोज करीब डेढ़ दर्जन सीसीटीवी कैमरे की खरीदारी की जा रही है वहीं हाईटेक सुरक्षा के बारे मे जानकारी लेने वालों की संख्या भी रोजाना दहाई तक पंहुच रही है। इस बढ़ती डिमांड का मुख्य कारण सुरक्षा की भावना है। लोगों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों मे मे खौफ तो रहता ही है,साथ ही यदि चोरी,लूट या अन्य कोई भी वारदात घटित भी होती है तो अपराधी की शिनाख्त और पहचान करना भी आसान हो जाता है।गृहस्थी और कारोबारी सुरक्षा के लिए लगाये गये इन तकनीकी उपकरणों से आये दिन पुलिस को भी बड़ी मदद मिलती है,बावजूद इसके शहर मे सीसीटीवी लगाने की प्रशासनिक तैयारी आज तक फाईलों से बाहर नहीं निकली।यद्यपि पुलिस का भी मानना है कि सीसीटीवी कैमरे लगने से शहर के प्रमुख व संवेदनशील स्थल पर आपराधिक वारदातों मे कमी जरुर आयेगी , क्योकिं कैमरे मे अपराधी की पूरी कारगुजारी उसकी तस्वीर के साथ कैद हो जायेगी ,जिससे उसकी धर पकड़ मे मदद मिलेगी।इसके अलावा सड़क दुर्घटना , अनियंत्रित स्पीड,और नियम - कायदे तोड़ती तमाम गतिविधियों की निगरानी आसान हो जायेगी। पूर्व मे जनभागीदारी से शहर के कुछ इलाकों मे लगाये गये सीसीटीवी कैमरों का लाभ आपराधिक घटना के दौरान पुलिस को मिलता रहा है।

सुरक्षा पर अर्थव्यवस्था भारी

पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह के मुताबिक शहर मे 40 ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बेहद आवश्यक है।एसपी ने इस आवश्यकता से राज्य शासन व गृह विभाग को भी अवगत कराया है किंतु आईपीएस की मानें तो सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शासन की ओर से फण्ड का प्रावधान न होने से पुलिस की इच्छाशक्ति के बावजूद सुरक्षा की अहम कड़ी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रही। हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुये एसपी संतोष कुमार बताते हैं कि एटीएम कैशवैन रॉबरी मे अपराधियों का सुराग लगाने मे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को बड़ी मदद मिली थी। वहीं कोरोना संक्रमण से निपटने की कवायद मे भी सीसीटीवी की निगरानी की मदद कारगर साबित हो रही है।

हथियार से ज्यादा कारगर कैमरे - एसपी

जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह का मानना है कि मौजूदा तकनीकी परिवेश मे हथियारों से ज्यादा तकनीकी यंत्र प्रभावशाली हैं। सीमित बल और पाबंद पुलिस पेट्रोलिंग के बूते जनसुरक्षा का एहसास तो कराया जा सकता है किंतु अपराधियों मे भय बढ़ाने के साथ पुलिस की मदद तो सीसीटीवी ज्यादा बेहतर कर सकती है।आईपीएस सिंह ने बताया कि सीसीटीवी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महानगरों मे केवल तीसरी आँख का पहरा बिठाने 3 से 5 सौ करोड तक का बजट प्रस्तावित किया गया है।

सीसीटीवी की मदद से सुलझे बड़े मामले

खरसिया मे एक दुकानदार से मारपीट कर जान से मारने वाले दस लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरे की मदद से संभव हो सकी। सभी आरोपी न केवल गिरफ्तार हुये बल्कि न्यायालय से उन्हे कठोर दण्ड भी सुनाया गया। तंत्रजाल मे फंसकर अपने ही बेटे की बलि देने वाले आरोपी की शिनाख्त भी व्यापारिक प्रतिष्ठान मे लगे सीसीटीवी से हुई थी। जिसके बाद उसे यूपी से गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई । शहर के पाश कालोनी और कोतरा रोड थाना क्षेत्र मे घटित सशस्त्र गैंगवार तथा लूट के आरोपी भी एक चिकित्सक के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से पहचाने और पकड़े गये। किरोडीमल नगर मे एटीएम कैशवैन रॉबरी मे शामिल अपराधियों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने मे बाजार के सीसीटीवी की मदद ली गई ।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480